पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2023 का आपराधिक विविध सं. 31499

थाना कांड संख्या-2 वर्ष-2018 थाना- विजिलेंस जिला- पटना से उत्पन्न

=====

1. वेद प्रकाश कर्णवाल, पुत्र- स्वर्गीय बिशंबर सहाय कर्णवाल, निवासी--हाउस नंबर 227/32, आर्य पुरी, अंसारी रोड, थाना---सिविल लाइन्स, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश राज्य।
2. उमा रानी कर्णवाल, पत्नी--वेद प्रकाश कर्णवाल, हाउस नंबर 227/32, आर्य पुरी, अंसारी रोड, थाना-- सिविल लाइन्स, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश राज्य।

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य, निगरानी के माध्यम से

.....विपरीत पक्ष

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री साकेत गुप्ता, अधिवक्ता
श्री मयंक शेखर, अधिवक्ता
श्री श्यामेश्वर कुमार सिंह, अधिवक्ता

एस.वी.यू. के लिए : श्री राणा विक्रम सिंह, विशेष लोक अभियोजक, निगरानी

=====

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—भारतीय दंड संहिता की धारा 109, धारा 13(2) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) के साथ पठित—संज्ञान आदेश को रद्द करना—याचिकाकर्ता मुख्य आरोपी के रिश्तेदार हैं—उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने मुख्य आरोपी की मिलीभगत से बिहार सरकार और आयकर विभाग से अवैध तरीकों से अर्जित आय/संपत्ति को छुपाया—याचिकाकर्ताओं की बेटी की संपत्ति, जो उसका स्त्रीधन था, को उसके पति (मुख्य आरोपी) की आय से अधिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और ऐसे कारणों से याचिकाकर्ता जो ससुर और सास हैं, को वर्तमान मामले में फंसाया गया—एफआईआर दर्ज करने से पहले कोई

प्रारंभिक जांच नहीं की गई जो बिहार सरकार के आदेश के अनुसार आवश्यक है-मुख्य आरोपी को अनुशासनात्मक कार्यवाही से मुक्त कर दिया गया था, और आयकर विभाग ने सभी छह वित्तीय वर्षों के पुनर्मूल्यांकन के बाद, याचिकाकर्ताओं की ओर से उनकी आय के संबंध में कोई अनियमितता नहीं पाई और इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने पहले ही इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन वापस लेने के लिए आवेदन दायर कर दिया है-अभियोजन वापस लेना याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 482—भारतीय दंड संहिता की धारा 109, धारा 13(2) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) के साथ पठित—संज्ञान आदेश को रद्द करना—याचिकाकर्ता मुख्य आरोपी के रिश्तेदार हैं—उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने मुख्य आरोपी की मिलीभगत से बिहार सरकार और आयकर विभाग से अवैध तरीकों से अर्जित आय/संपत्ति को छुपाया—याचिकाकर्ताओं की बेटी की संपत्ति, जो उसका स्त्रीधन था, को उसके पति (मुख्य आरोपी) की आय से अधिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और ऐसे कारणों से याचिकाकर्ता जो ससुर और सास हैं, को वर्तमान मामले में फंसाया गया—एफआईआर दर्ज करने से पहले कोई प्रारंभिक जांच नहीं की गई जो बिहार सरकार के आदेश के अनुसार आवश्यक है-मुख्य आरोपी को अनुशासनात्मक कार्यवाही से मुक्त कर दिया गया था, और आयकर विभाग ने सभी छह वित्तीय वर्षों के पुनर्मूल्यांकन के बाद, याचिकाकर्ताओं की ओर से उनकी आय के संबंध में कोई अनियमितता नहीं पाई और इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने पहले ही इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन वापस लेने के लिए आवेदन दायर कर दिया है-अभियोजन वापस लेना याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कुछ है, जहां विवादित संज्ञान आदेश पर 'स्थगन' का अर्थ केवल कुछ ऐसा रोकना है जो याचिकाकर्ताओं को मजबूर कर सकता है, अगर कार्यवाही को आगे बढ़ने दिया जाता है- याचिकाकर्ताओं के पक्ष में योग्यता के संतुलन को देखते हुए वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के संबंध में कार्यवाही रोक दी गई थी-याचिका को अनुमति दी जाती है।

(पैरा 22, 26, 35, 34, 36)

एआईआर 2005 एससी 359; 2016 एससीसी ऑनलाइन एससी 1006; (1992) अनुपूरक (1) एससीसी 335-पर भरोसा किया गया।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

सी. ए. वी. निर्णय

तिथि : 19-03-2025

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, श्री साकेत गुप्ता और राज्य सतर्कता इकाई (संक्षेप में 'एस. वी. यू.') के लिए विशेष लोक अभियोजक, श्री राणा विक्रम सिंह को सुना।

2. वर्तमान याचिका, विद्वान विशेष न्यायालय,पटना के 23.01.2023 के संज्ञान आदेश को रद्द करने के लिए दाखिल की गई है,जो दर्ज प्राथमिकी, विशेष वाद संख्या-02/2018 जो दिनांक -15.04.2018 को भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए,जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) और 13(1) के साथ पठित है, जो वर्तमान में विद्वान विशेष न्यायाधीश, निगरानी, पटना के न्यायालय में लंबित है, दर्ज की जा रही है।

3. उपरोक्त प्राथमिकी,राम राज्य शर्मा पुलिस उपाधीक्षक/ विशेष निगरानी इकाई/पटना की लिखित रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, श्री विवेक कुमार, भारतीय पुलिस सेवा, (बिहार,2007) जो वर्तमान में बिहार के मुजफ्फरपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात हैं, पर आरोप लगाया गया है कि वह एक भ्रष्ट अधिकारी हैं और उन्होंने भ्रष्ट तरीकों से भारी चल और अचल संपत्ति अर्जित की है, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है।

4.आरोप है कि श्री विवेक कुमार, जिनका जन्म 01.07.1978 को हुआ, पुत्र श्री प्रकाश चंद्र, निवासी 31, वरुण विहार, दिल्ली रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 18.08.2007

को भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। श्री विवेक कुमार एक वर्ग /ग्रेड-ए अधिकारी हैं, जो बिहार के पूर्णिया, जहानाबाद, नौगछिया, सीतामढ़ी, सीवान, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में विभिन्न पदों पर तैनात रहे। उन्होंने 1994 में सेंट मैरीज़ अकादमी, सहरनपुर से हाई स्कूल पास किया और और आई. आई. टी. रुडकी से बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) किया। इसके बाद उन्होंने आयकर विभाग में भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी के रूप में कुछ वर्षों तक काम किया, उसके बाद वे बिहार कैडर में भारतीय पुलिस सेवा (2007) के अधिकारी के रूप में शामिल हुए। उनका विवाह 06.12.2010 को श्रीमती निधि कर्णवाल के साथ हुआ। श्रीमती निधि कर्णवाल श्रीमती उमा रानी कर्णवाल (याचिकाकर्ता संख्या 2) और श्री वेद प्रकाश कंवल (याचिकाकर्ता संख्या 1) की पुत्री हैं। (0) मकान संख्या 227/32 ए, अंसारी रोड, आर्यपुरी, मुजफ्फरनगर (उप्र) (ii) 87 सरवत उत्तर, मुजफ्फरनगर (उप्र)/87 सरवत रोड, केवल पुरी, सिविल लाइंस उत्तर, मुजफ्फरनगर (उप्र) और (ii) 67/5 बाग केशो दास, सनातन धर्म सभा के पास, मुजफ्फरनगर (उप्र) की निवासी हैं। निधि कर्णवाल @ निधि विवेक एक गृहिणी हैं। श्री विवेक कुमार और श्रीमती निधि कर्णवाल का एक बेटा रेयांश है। श्री वेद प्रकाश कर्णवाल (याचिकाकर्ता संख्या 1) (श्रीमती निधि कर्णवाल के पिता और श्री विवेक कुमार के ससुर) जनवरी, 2009 से सेवानिवृत्त हैं, यानी श्री विवेक कुमार और श्रीमती निधि कर्णवाल के विवाह से पहले। श्रीमती उमा रानी कर्णवाल (याचिकाकर्ता संख्या 2), श्रीमती निधि कर्णवाल की मां एक गृहिणी हैं। श्रीमती निधि कर्णवाल के भाई श्री निखिल कर्णवाल हैं। परिवार के अन्य सदस्य श्रीमती शेली कर्णवाल और श्रीमती पूनम कर्णवाल हैं।

5. यह आरोप लगाया गया है कि श्री विवेक कुमार ने पूर्णिया और जहानाबाद में अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी और नवगछियानौगछिया, सीतामढ़ी, सीवान, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात रहते

हुए, अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान एक लोक सेवक के रूप में भ्रष्ट आचरण किया। श्री विवेक कुमार ने अपनी पत्नी श्रीमती निधि कर्णवाल, सास- उमा रानी कर्णवाल (याचिकाकर्ता संख्या 2), ससुर श्री वेद प्रकाश कर्णवाल (याचिकाकर्ता संख्या 1), बहनोई श्री निखिल कर्णवाल और रिश्तेदार श्रीमती शेली कर्णवाल के नाम पर मुजफ्फरनगर (यू. पी.) में भारी चल और अचल संपत्तियाँ जमा कीं, जैसा कि विश्वसनीय स्रोतों से पता चला है। यह भी पता चला है कि विवेक कुमार ने अपनी पत्नी श्रीमती निधि कर्णवाल@निधि विवेक, के माता-पिता, भाई और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर भारतीय स्टेट बैंक, अंसारी रोड शाखा, मुजफ्फरनगर (यू. पी.) में सावधि जमा बनाने के लिए भारी खर्च किया था। प्राथमिकी में विवेक कुमार और श्रीमती निधि कर्णवाल के ज्ञात/घोषित और अघोषित स्रोतों से आय की सूची भी शामिल है। श्रीमती निधि कर्णवाल, जिनका विवरण दर्ज प्राथमिकी के विभिन्न पृष्ठों में दिया गया है।

6. यह भी आरोप लगाया गया है कि श्री विवेक कुमार और श्रीमती निधि कर्णवाल के रिश्तेदार के पास इतनी बड़ी संपत्ति की उपलब्धता को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त आय नहीं थी, भले ही यह माना जाता है कि विवेक कुमार, निधि कर्णवाल और उनके रिश्तेदारों ने पैरा-12 (i) में उल्लिखित अवधि के दौरान शून्य खर्च किया था, उनके द्वारा (विवेक कुमार और निधि कर्णवाल सहित) 2,06,94,238/- की चल संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था, जबकि सकल आय रु 1,56,42,164/- है, का किसी भी तरह से संतोषजनक रूप से हिसाब नहीं किया जा सकता है।

7. यह भी आरोप लगाया गया है कि उपरोक्त संपत्तियाँ जो केवल चल हैं, वास्तव में, विवेक कुमार और श्रीमती निधि कर्णवाल के नाम 2012 में अधिग्रहित अचल संपत्तियाँ हैं। जिनका उपरोक्त गणना में उल्लेख नहीं किया गया है। इसके

अलावा, सूचना के स्रोत के अनुसार, यह उचित रूप से माना जाता है कि जांच के दौरान उपरोक्त व्यक्तियों के नाम पर और अधिक संपत्तियां मिलने की संभावना है।

8. यह कि श्रीमती निधि कर्णवाल और उनके रिश्तेदार श्री वेद प्रकाश कर्णवाल (याचिकाकर्ता संख्या 1), श्रीमती उमा रानी कर्णवाल (याचिकाकर्ता संख्या 2), श्री निखिल कर्णवाल और श्रीमती शेली कर्णवाल ने विवेक कुमार के साथ उक्त साजिश में सक्रिय रूप से हाथ मिलाया है। वास्तव में, श्री विवेक कुमार ने एक लोक सेवक के रूप में अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भ्रष्ट तरीके से अवैध लाभ अर्जित किया। श्रीमती निधि कर्णवाल और उनके रिश्तेदारों ने श्री विवेक कुमार द्वारा अर्जित अवैध लाभ को विचारपूर्वक और जानबूझकर अपने नाम में चल संपत्तियों के अधिग्रहण के माध्यम से निवेश किया। श्री विवेक कुमार, ने श्रीमती निधि कर्णवाल और उनके रिश्तेदारों की सहायता से बिहार सरकार और आयकर विभाग से अवैध माध्यमों से अर्जित आय/संपत्ति को छुपाया। कार्य में ऐसी चूक /या दलाली के कार्यों के लिए, श्री विवेक कुमार के अवैध लाभ के अधिग्रहण में श्रीमती निधि कर्णवाल और उनके रिश्तेदार ,कदाचार के लिए समान रूप से उत्तरदायी हैं।

9. आगे यह आरोप लगाया गया कि केवल श्री विवेक कुमार और उनकी पत्नी श्रीमती निधि कर्णवाल द्वारा एक साथ अधिग्रहित संपत्ति पर एक नज़र, या अपने परिवार के सदस्यों के साथ, इस अटूट और निर्विवाद निष्कर्ष पर पहुँचेंगी कि श्री विवेक कुमार और उनकी पत्नी को एक साथ, उनके अन्य रिश्तेदारों के साथ ही साथ लिया गया, जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है, जिसका किसी भी तरह से संतोषजनक हिसाब नहीं दिया जा सकता है।

10. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदित है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान अभिलेख पर उपलब्ध तत्वों को जाने बिना,

उपरोक्त प्राथमिकी में लिया गया था, विशेष रूप से आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेख (संक्षेप में "आईटी विभाग") क्योंकि जांच के दौरान, जांच अधिकारी ने मामले को आयकर विभाग को यह पता लगाने के लिए भेजा है कि क्या प्राथमिकी के माध्यम से लगाया गया आरोप याचिकाकर्ताओं की वास्तविक आय है, जिसके बाद आयकर विभाग ने याचिकाकर्ताओं और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयकर विभाग के उपरोक्त अभिलेख को जानबूझकर केस डायरी का हिस्सा नहीं बनाया गया और याचिकाकर्ताओं को परेशान करने के उद्देश्य से, यहां तक कि जांच के दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त किए बिना भी, इसी रवैये के साथ अप्रत्यक्ष रूप से, कोई कारण बताए बिना आरोप पत्र दायर किया गया।

11. यह बताया गया है कि आयकर विभाग की उक्त रिपोर्ट को इसे विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष भी लाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से इस पर विचार नहीं किया गया और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान का विवादित आदेश पारित किया गया।

12. आगे यह तर्क देते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के दामाद, जबकि 2017 में मुजफ्फरपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात थे, को 05.10.2017 को भारत सरकार के मानव संसाधन विभाग के माननीय राज्य मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी के पद के लिए चुना गया था, और उस कार्य के लिए उन्हें निगरानी विभाग, बिहार सरकार द्वारा निगरानी मंजूरी दी गई थी और उक्त उद्देश्य के लिए 5 मार्च, 2018 को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' भी दिया गया था।

13. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब याचिकाकर्ताओं के दामाद के बारे में उपरोक्त तथ्य तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई. के संज्ञान में आया, जो पहले पुलिस अधीक्षक., मुजफ्फरपुर के रूप में तैनात थे और याचिकाकर्ताओं

के दामाद के कार्य और पदोन्नति के साथ पक्षपाती थे, तो उन्होंने एक साजिश रची और वरिष्ठ प्राधिकारी को भ्रामक जानकारी दी, जिसमें वर्तमान अभियोजन दर्ज किया गया था और याचिकाकर्ताओं के दामाद से उनकी संपत्ति के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था, जिसे उनके द्वारा पहले ही घोषित किया जा चुका है।

14. इस संदर्भ में, यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के दामाद ने अपने नौकरी में शामिल होने के बाद से, हर साल अपनी सभी वार्षिक संपत्तियों और देनदारियों को घोषित किया और इसलिए, याचिकाकर्ताओं की बेटी के सभी स्निधन को अवैध मानने के बाद कोई प्रारंभिक जांच किए बिना, वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

15. आगे तर्क देते हुए, विद्वान अधिवक्ताद्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्राथमिकी के तत्वों के साथ-साथ उसमें उल्लिखित आय और व्यय के आंकड़ों के अवलोकन से यह पता चला है कि दुर्भावनापूर्ण इरादे से, विशेष निगरानी इकाई ने सुनवाई का अवसर दिए बिना, ₹-72,69,779 को याचिकाकर्ताओं के दामाद की आय से अधिक संपत्ति के रूप में दर्ज किया और उनके द्वारा प्रस्तुत आईटीआर के आधार पर इसे वार्षिक घोषित संपत्ति तय किया। याचिकाकर्ताओं की बेटी के स्निधन और उसकी सभी घोषित संपत्तियों को अवैध माना गया है और केवल यह कारण बताते हुए कि वह एक गृहिणी है, आय से अधिक संपत्ति के हिस्से के रूप में लिया गया है।

16. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त अनुमानित टिप्पणी के आधार पर, याचिकाकर्ताओं की बेटी की संपत्ति, जो उसकी स्निधन थी, को उसके पति की आय से अधिक संपत्ति घोषित किया गया था और ऐसे कारणों से याचिकाकर्तागण जो ससुर और सास हैं, को वर्तमान मामले में फंसाया गया था। यह बताया गया है कि विशेष निगरानी इकाई द्वारा याचिकाकर्ताओं को आज तक कोई प्रश्नावली जारी नहीं की गई है।

ताकि वे प्रश्न का उत्तर दे सकें। इस संबंध में सरकारी नीति की ओर इशारा करते हुए, यह निवेदित किया जाता है कि बिहार सरकार ने अपने दिनांक 29.08.2008 विभा०/स्था.०/विविध पत्र सं/619/2005/4927 में अपने सभी विभागीय प्रमुख को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि सभी कर्मचारियों की चल/अचल संपत्ति वापसी की पहले जांच की जानी चाहिए और यदि उनमें से कोई भी संदिग्ध पाया जाता है, तो कोई भी कार्रवाई शुरू करने से पहले एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान मामले में विशेष निगरानी इकाई गलत और अप्रत्यक्ष उद्देश्य से सीधे प्राथमिकी दर्ज की है।

17. यह आगे तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता सं- 1 ने इस वाद के प्रभारी अधिकारी. से उनके हृदय की समस्या और उनकी पत्नी(याचिकाकर्ता सं.2) की घुटने की गंभीर समस्या और देश में प्रचलित कोविड-19 स्थिति की पृष्ठभूमि में, विशेष निगरानी इकाई के कारण जवाब देने के लिए एक प्रश्नावली भेजने का अनुरोध किया ,लेकिन. प्रभारी अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं को कोई प्रश्नावली नहीं भेजी ताकि वे विशेष निगरानी इकाई. के प्रश्न का उत्तर दे सकें। विशेष निगरानी इकाई. का यह रवैया परेशान करने वाला था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रारंभिक जांच, जो एक अनिवार्य प्रावधान है, वर्तमान मामले में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले नहीं किया गया था और इसलिए, वर्तमान प्राथमिकी स्वयं विधि की नजर में गलत है।

18. आगे तर्क देते हुए, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ताओं के दामाद के विरुद्ध मार्च 2019 में एक अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे बिहार के मुख्य जांच आयुक्त द्वारा संचालित किया गया था, जिसमें सभी तथ्य और साक्ष्य उनके द्वारा प्रदान किए गए थे, जिस पर विचार करने पर, याचिकाकर्ता के दामाद को आय से अधिक

संपत्ति के आरोप सहित विभागीय कार्यवाही में आरोप मुक्त किया गया था और इसे दिसंबर, 2020 में आगे की कार्यवाही के लिए गृह विभाग को प्रस्तुत किया गया था। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जब याचिकाकर्ताओं के दामाद ने विभागीय जांच रिपोर्ट पर निर्णय के लिए माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना (संक्षेप में 'कैट') में एक मामला दायर किया, तो दिसंबर 2021 में इस याचिका पर एक नई जांच शुरू करने का आदेश दिया गया कि विशेष निगरानी इकाई ने अभियोजन मंजूरी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसे विशेष निगरानी इकाई द्वारा अपनी जांच और आगे की कार्यवाही के लिए आयकर विभाग.जांच शाखा, मेरठ ने बाद में याचिकाकर्ता को दिनांक 23.02.2021 के समन के माध्यम से, याचिकाकर्ता स०-1, से पुरी जानकारी मंगाई, जो विशेष निगरानी इकाई बिहार द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित था। इसके बाद, याचिकाकर्ता स०-1 ने आयकर विभाग शाखा, मेरठ की प्रश्नावली का विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया, जिसने अपनी जांच के बाद याचिकाकर्ता संख्या 1 के मामले में लगातार 6 वर्षों के लिए मूल्यांकन मामलों को फिर से खोलने की सिफारिश की। लगातार पाँच वर्षों के लिए मूल्यांकन आदेश अर्थात् वित्त वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17, जो जाँच के बाद, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उनकी आय और संपत्ति के संबंध में किसी भी विसंगति के साथ नहीं पाए गए। आयकर विभाग के उपरोक्त निष्कर्ष को विस्तृत आयकर निर्धारण आदेशों की प्रतियों के साथ अतिरिक्त महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई को सूचित किया गया था, लेकिन इस मामले के जांच अधिकारी ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इस संदर्भ में, यह आगे निवेदित है कि 06.03.2023 पर, आयकर विभाग ने याचिकाकर्ता संख्या-2 के लिए छठे मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए भी विस्तृत मूल्यांकन आदेश जारी किया और याचिकाकर्ताओं की आय को वास्तविक पाया और वर्तमान मामले से संबंधित नहीं पाया।

19. यह निवेदित है कि *प्रथम दृष्टया* ऐसे सभी तथ्य विभागीय पक्षपात के कारण अप्रत्यक्ष और परोक्ष अभियोजन है, जहां याचिकाकर्ताओं को संबंधित अधिकारी के ससुराल वाले होने के कारण परेशान करने वाले रवैये का शिकार बनाया गया था।

20. इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयकर विभाग से आरोप मुक्त किये जाने के बाद और याचिकाकर्ताओं के दामाद को विभागीय कार्यवाही से दोषमुक्त करने के बाद, वर्तमान कार्यवाही को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है।

21. तर्क का समापन करते हुए, विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि याचिकाकर्ताओं के दामाद, विवेक कुमार ने समय-समय पर अपनी पत्नी, जो याचिकाकर्ताओं की बेटी है, के स्त्रीधन उपहार को को बिहार सरकार के साथ और आयकर विभाग के साथ भी घोषित किया, जिसे आयकर विभाग द्वारा जांच पर प्रमाणित किया गया था, जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने, उनके दामाद को उनकी संपत्ति के गठन के लिए एक भी रुपया नहीं दिया था और इसलिए, *प्रथम दृष्टया*, याचिकाकर्ताओं के केवल ससुराल वाले होने के निहितार्थ, उनके अभियोजन के लिए आरोप के अनुसार कोई मामला नहीं बनता है। याचिकाकर्ताओं का आशय केवल अपने दामाद को गलत और अप्रत्यक्ष विभागीय उद्देश्य से परेशान करना है।

22. विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क करते हुए, यह निवेदित है कि उपरोक्त गलती को महसूस करते हुए विभाग (विशेष निगरानी इकाई.) ने दिनांक 02.09.2024 को, याचिकाकर्ताओं पक्ष के ऊपर वर्तमान अभियोजन को वापस लेने के लिए विशेष न्यायाधीश, निगरानी, पटना के न्यायालय में एक आवेदन दायर किया और इसलिए, अब याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इस मामले में कुछ भी नहीं बचा है। यह इंगित किया

गया है कि सितंबर, 2024 से, यह मामला न्यायालय के समक्ष केवल एक ही कारण से नीचे दी गई उक्त याचिका पर आदेश हेतु लंबित है क्योंकि, याचिकाकर्ताओं के संज्ञान आदेश पर इस न्यायालय ने अपने दिनांक 10.11.2023 के आदेश के माध्यम से रोक लगा दी थी।

23. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह निवेदित है कि, विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं के लिए कार्यवाही जारी रखना केवल न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के बराबर होगा और इसलिए, इसे अलग करने/रद्द करने के लिए उपयुक्त है।

24. पटना उच्च न्यायालय की ओर से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक निगरानी, श्री राणा विक्रम सिंह ने इस मामले में बहस करते हुए कहा कि अभियोजन के उपरोक्त वापसी पत्र को देखते हुए, वर्तमान याचिका फलहीन हो जाती है।

25. यह एक स्वीकृत परिस्थिति है कि जो मुख्य भ्रष्टाचार के आरोप विवेक कुमार के विरुद्ध उपलब्ध है, जो एक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और छापे के समय उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के रूप में तैनात किया गया था, जो याचिकाकर्ताओं से, दामाद के रूप में संबंधित हैं। वर्तमान वाद, याचिकाकर्ताओं के निहितार्थ भा.द.स.. की धारा 107/109 की सहायता से प्रकट होता है। उपरोक्त चर्चा से आरोप का सार सामने आया कि विवेक कुमार की पत्नी निधि विवेक @निधि कर्णवाल, का स्त्रीधन, जिसे इन याचिकाकर्ताओं की आय से असमान बताया गया था और इसलिए, यह आरोप लगाया गया था कि निधि कर्णवाल की संपत्ति, विवेक कुमार के भ्रष्ट आचरण करते हुए बनाई गई थी, जिसके बाद विवेक कुमार ने, जहां इन याचिकाकर्ताओं की भूमिका दुष्प्रेरक की होने के नाते, यह स्वीकार करते हुए कि निधि विवेक @निधि कर्णवाल द्वारा दिखाई गई स्त्रीधन राशि उकसाने वाली प्रतीत होती है।

मुख्य आरोपी विवेक कुमार, जो भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी हैं, के साथ उसकी शादी के अवसर पर याचिकाकर्ताओं द्वारा स्त्रीधन के रूप में दिया गया था।

26. मुख्य सह-अभियुक्त विवेक कुमार को बिहार सरकार द्वारा विभागीय कार्यवाही से दोषमुक्त कर दिया गया। अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले कोई प्रारंभिक जांच नहीं की गई थी जोकि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है बिहार सरकार के 29.08.2008. के आदेश के संदर्भ में आवश्यक है।

27. भा०द०स०. की धारा 107 और 109 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो निम्नानुसार है:

“107. किसी बात का दुष्प्रेरण— एक व्यक्ति किसी बात के किये जाने का दुष्प्रेरण करता है, जो -

पहला— उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है; या

दूसरा— उस बात को करने के लिए किसी भी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में, और उस बात को करने के उद्देश्य से, कोई कार्य या अवैध लोप घटित को जाये, या

तीसरा— जानबूझकर किसी कार्य या अवैध चूक द्वारा उस कार्य को करने में सहायता करना।

स्पष्टीकरण 1.— कोई व्यक्ति जो जानबूझकर गलत बयानी करके या जानबूझकर किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर, जिसे प्रकट करने के लिए वह बाध्य है, स्वेच्छा से किसी कार्य को करवाता है या करवाता है या करवाने या करवाने का प्रयास करता है, उसे उस कार्य को करने के लिए उकसाने वाला कहा जाता है।”

“109. दुष्प्रेरण के लिए दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो और उसके दण्ड के लिए कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं किया गया हो।--जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण

करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए इस संहिता द्वारा कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं किया गया हो, तो उसे उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण--किसी कार्य या अपराध को दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब कहा जाता है, जब वह उकसावे के परिणामस्वरूप या षड्यन्त्र के अनुसरण में या दुष्प्रेरण का गठन करने वाली सहायता से किया गया हो।"

28. उपरोक्त आरोप की पृष्ठभूमि में, आयकर विभाग. जांच शाखा, मेरठ ने इन याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध, विशेष निगरानी इकाई ,बिहार से प्राप्त शिकायत के आधार पर, याचिकाकर्ता सं.-1 के वर्ष 2012-13,2013-14,2014-15,2015-16 और 2016-17, अर्थात् उपरोक्त छह वित्तीय वर्ष के पुनर्मूल्यांकन का आदेश वर्ष 2022 में आयकर विभाग द्वारा पारित किया गया था, जिसमें इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उनकी आय और संपत्ति के संबंध में कोई विसंगतियां नहीं पाई गईं, जैसा कि विशेष निगरानी इकाई के वर्तमान मामले से जुड़ा हुआ है। उपरोक्त आयकर विभाग के निष्कर्ष को विशेष निगरानी इकाई ,बिहार को भी 06.03.2023 को सूचित कर दिया गया था, आयकर विभाग ने याचिकाकर्ता संख्या-1 के लिए छठे वित्तीय वर्ष यानी 2018-19 के लिए भी विस्तृत मूल्यांकन आदेश जारी किया जो वास्तविक भी पाया गया, जिसका विवरण याचिका के अनुलग्नक '10' और '11' के माध्यम से उपलब्ध है, इन दस्तावेजों की शुद्धता और वास्तविकता अभेद्य और उत्कृष्ट प्रकृति की प्रतीत होती है, इसलिए, **उड़ीसा राज्य बनाम देवेंद्रनाथ पट्टि (ए.आई.आर..2005 एस. सी. 359 में रिपोर्ट किया गया,)** के माध्यम से उपलब्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विधिक प्रतिवेदन को देखते हुए वर्तमान याचिका पर विचार करते समय इन दस्तावेजों को पढ़ने में कोई संकोच नहीं है।

29. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि भा०द०स० की धारा 109 के लिए, केवल एक षड्यंत्र दिखाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्य किया गया है जो प्रमाणित किया जाना चाहिए। भा०द०स० की धारा 109 के साफ-सुथरे पाठ में कहा गया है कि दुष्प्रेरक उसी सजा के लिए उत्तरदायी है जो प्रमुख अपराधी पर लगाई जा सकती है, यदि मुख्य अपराधी का कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है। [सोमसुंदरम उर्फ सोमू बनाम राज्य ,पुलिस उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत (2016 एस. सी. सी.2016 ऑनलाइन--एस. सी. 1006 में रिपोर्ट किया गया)।

30. याचिकाकर्ताओं के पक्ष में उपलब्ध योग्यता के अलावा, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, जो याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया कि अभियोजन पक्ष ने 02.09.2024 को याचिकाकर्ताओं की वर्तमान रद्द करने वाली याचिका को वापस लेने के लिए एक आवेदन को प्राथमिकता दी, जिसे विशेष निगरानी इकाई की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री राणा विक्रम सिंह द्वारा विवादित नहीं किया जा सका।

31. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के निवेदन करने से, ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले छह महीनों से अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त याचिका दायर विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है, लेकिन चूंकि इस न्यायालय के दिनांक 10.11.2023 के आदेश के अनुसार संज्ञान आदेश को आगे बढ़ाने में याचिकाकर्ताओं की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए अब तक इसका निर्णय नहीं किया गया था।

32. यह न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि विवादित संज्ञान आदेश पर रोक का आदेश, अभियोजन वापस लेने के रूप में कैसे आया। अभियोजन वापस लेना जहाँ तक कुछ याचिकाकर्ताओं के पक्ष में है, जहां आक्षेपित संज्ञान आदेश की 'रोक' का

तात्पर्य केवल कुछ ऐसी तत्वों/आदेश को रोकने के लिए है, जो याचिकाकर्ताओं को मजबूर कर सकती है, अगर कार्यवाही को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ताओं के पक्ष में विद्यमान तथ्यों के संतुलन को देखते हुए वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी।

33. माननीय उच्चतम न्यायालय की विधिक रिपोर्ट के पैरा 102 को यथासंभव हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजनलाल और अन्य (1992(सु०को०)-(1) एस. सी. सी. 335 में रिपोर्ट किया गया),के माध्यम से पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जिसे तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है:

‘102. संहिता के अध्याय XIV के अधीन विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, हम निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को उदाहरण के रूप में देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा, न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से व्यवस्थित और लचीले दिशानिर्देशों को निर्धारित करना, या कठोर सूत्र और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना जिसमें इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, संभव नहीं हो सकता है।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के विरुद्ध मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और अन्य तत्व, यदि कोई हो, प्राथमिकी के साथ एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, और, संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश को छोड़कर, संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।

(3) जहां प्राथमिकी या परिवाद में किए गए अविवादित अभिकथन और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध मामला बनाते हैं।

(4) जहां प्राथमिकी में अभिकथित आरोप , संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते ,केवल असंज्ञेय अपराध गठित करते हैं, वहां बिना दंडाधिकारी के आदेश के पुलिस अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 155 (2) के अधीन अन्वेषण की अनुज्ञा नहीं दी जाती है।

(5) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि उनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस न्यायसंगत निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही को जारी रखने और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, वहां पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट विधिक रोक है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहाँ अभियुक्तों से प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण ढंग से और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण कार्यवाही शुरू की जाती है ।”

34. उपरोक्त के मद्देनजर, चूंकि मुख्य अभियुक्त विवेक कुमार विभागीय कार्यवाही से दोषमुक्त प्रतीत होता है, जहां आयकर विभाग, मेरठ ने सभी छह वित्तीय वर्षों के पुनर्मूल्यांकन के बाद, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, याचिकाकर्ताओं की ओर से उनकी आय के संबंध में कोई अनियमितता नहीं पाई और इसके अलावा, अभियोजन पक्ष ने पहले ही इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया है, तदनुसार, भजन लाल के मामले (सुप्रा) के पैरा 102 के क्रम संख्या 3, 5 और 7 पर मार्गदर्शक नोट लेते हुए, विशेष सतर्कता इकाई केस संख्या

02/2018 दिनांक 15.04.2018 के अनुरूप विशेष मामला संख्या 19/2018 में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (सतर्कता) द्वारा याचिकाकर्ताओं के संबंध में पारित संज्ञान आदेश दिनांक 23.01.2023 को अपास्त /रद्द किया जाता है।

35. लंबित याचिका, यदि कोई हो, का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

36. इस रद्दीकरण याचिका स्वीकृत की जाती है।

37. इस निर्णय की एक प्रति इसके अनुपालन के लिए तुरंत विद्वत विचारण न्यायालय को भेजी जाए।

(न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा,)

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।